International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.10 No.2 Nov – Dec 2022

भारत-श्रीलंका का राजनीतिक संबंध

डॉ० रमेश प्रसाद कोल
सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग,
शासकीय आर.व्ही.पी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला उमरिया म०प्र०. भारत, ४८४६६१
Corresponding Author- डॉ० रमेश प्रसाद कोल
Email:- dr.rameshprasadkol@gmail.com

सारांश

भारत-श्रीलंका संबंधों में पिछले तीस वर्षों में कई बदलाव आए हैं। श्रीलंका की आंतरिक राजनीतिक स्थिति और उस पर भारत की प्रतिक्रिया ने ज्यादातर द्विपक्षीय संबंधों को आकार दिया है। साथ ही, दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय मंचों, जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक), के माध्यम से एक-दूसरे के साथ जुड़ने के प्रयास किए हैं। भारत की “पड़ोसी पहले की नीति” के साथ-साथ श्रीलंका की ष्भारत पहले नीतिष ने श्रीलंका में सरकार बदलने के बावजूद हाल के वर्षों में संबंधों में निरंतरता बनाए रखी है। इस संदर्भ में भारत में श्रीलंकाई उच्चायोग द्वारा अगस्त २०२१ में जारी श्रीलंका की एकीकृत राष्ट्र रणनीति (आईसीएस) पत्र, जो अगले दो वर्षों (२०२१-२३) के लिए एक रोड मैप है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौजूदा द्विपक्षीय मुद्दों पर नज़र रखता है और सहयोग के उन नए क्षेत्रों पर प्रस्ताव भी देता है जिनपर काम किया जा सकता है। यह भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में श्रीलंका के दृष्टिकोण को लेकर एक परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करता है।

मूल शब्दः- भारत, श्रीलंका, राजनीति

प्रस्तावना

भारत और श्री लंका के सम्बन्ध बहुत प्राचीन हैं और सामान्यतः मैत्रीपूर्ण रहे हैं। किन्तु श्रीलंकाई गृहयुद्ध के समय सम्बन्ध प्रभावित हुए थे। भारत, श्री लंका का एकमात्र पड़ोसी है। दक्षिण एशिया में दोनों देशों की स्थिति रणनीतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की इच्छा हिन्द महासागर में एक उभयनिष्ट सुरक्षा घेरा बनाने की है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों देश एक-दूसरे के अत्यन्त निकट रहे हैं। श्री लंका के ७० प्रतिषत नागरिक अब भी थेरावाद के अनुयायी हैं। दक्षिण एशिया में हिन्द महासागर के उत्तरी भाग में स्थित दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में एक श्रीलंका इन दिनों गहरे संकट में है। दो करोड़ २० लाख की आबादी वाला यह देश सबसे खराब आर्थिक और राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। कर्ज में डूबे इस देश के हालात इतने खराब हो गए हैं कि नाराज लोग सड़कों पर उतर आए हैं और देश की सरकार बदलने की लगातार मांग कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच के रिश्ते आज से नहीं बल्कि कई सौ साल पुराने हैं। श्रीलंका और भारत दो अलग-अलग देश होते हुए भी पौराणिक कथाओं के आधार पर जुड़े हुए हैं। कई प्रचलित कथाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर रिश्ते सदियों पुराने हैं। श्रीलंका में रह रहे हिन्दुओं की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग १२.६० प्रतिशत है। एक रिसर्च की मानें तो श्रीलंका की प्रमुख जाति सिंघल है और इस सिंघल जाति का संबंध उत्तर भारत के लोगों से है। सिंघल भाषा गुजराती और सिंधी भाषा जैसी ही है। भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी महज १८ मील है। भारत-श्रीलंका देश का लगभग ३००० वर्षों का संबंध है।

भारत-श्रीलंका का राजनीतिक संबंध

आर्थिक संबंधों में जिस तरह श्रीलंका चीन के क़रीब जा रहा है, उससे भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय साझेदारी के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। भारत और श्रीलंका के संबंध दोनों देशों की स्वतंत्रता के समय से दोस्ताना और अपेक्षाकृत स्थायी रहे हैं। लिबरेशन टाइगर्स अहफ़ तमिल ईलम (एलटीटीई) के बाद के युग में दोनों पड़ोसी सुरक्षा और आर्थिक उद्देश्यों में एक

साथ रहे हैं। इन उद्देश्यों में हिंद महासागर क्षेत्र में नौपरिवहन की स्वतंत्रता, आतंकवाद के ख़तरे का मुक़ाबला करना और समृद्ध दक्षिण एशियाई पड़ोस की ओर काम करना शामिल है. लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों की साझेदारी में ताज़गी की ज़रूरत है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक समर्थन के लिए श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ़ हो गया है और वो घरेलू आर्थिक विकास के लिए चीन को ज़्यादा भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है। श्रीलंका और चीन के बीच द्विपक्षीय साझेदारी की स्थिति को लेकर भारत में चिंता व्याप्त है। श्रीलंका के साथ चीन की नज़दीकी को भारत इस द्वीपीय देश में अपने असर के कमज़ोर होने की तरह देखता है। श्रीलंका की नौसेना के द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या के साथ-साथ भारत को मिले ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बंदरगाह ठेके को रद्द करने जैसे मामलों ने इन चिंताओं में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा, राजपक्षे परिवार के नेतृत्व में श्रीलंका की सरकार ऐतिहासिक तौर पर भारत के मुक़ाबले चीन के नज़दीक मानी जाती रही है और इन घटनाओं ने भारत और उसके सहयोगियों को इंडो-पैसिफिक सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता में डाल दिया है। मिसाल के तौर पर वहल स्ट्रीट जर्नल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़ चीन कोलंबो के नज़दीक श्रीलंका के समुद्र तट के किनारे १३ अरब अमेरिकी डहलर की लागत से एक शहर बनाने की शुरुआत करने जा रहा है।

राजपक्षे परिवार के नेतृत्व में श्रीलंका की सरकार ऐतिहासिक तौर पर भारत के मुक़ाबले चीन के नज़दीक मानी जाती रही है और इन घटनाओं ने भारत और उसके सहयोगियों को इंडो-पैसिफिक सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता में डाल दिया है। इसलिए उद्देश्यों और हितों में समानता के बावजूद भारत और श्रीलंका के लिए सावधानीपूर्वक और सोच-समझकर अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को फिर से जीवित करने की तत्काल ज़रूरत है।

चीन का दबदबा

पिछले कुछ वर्षों में इस द्वीपीय देश में चीन की पहुंच में नाटकीय ढंग से बढ़ोतरी हुई है। श्रीलंका ने दो वजहों से चीन को गले लगाया है। पहली वजह ये है कि तमिल मुद्दे के बारे में भारत की नीयत को लेकर श्रीलंका का शक बना हुआ है। दूसरी वजह भारत में नौकरशाही की प्रक्रिया की धीमी रफ़्तार है जो किसी मंज़ूरी में देर लगाती है। इसके कारण श्रीलंका को लेकर भारत की प्रतिबद्धता वहां संदेह पैदा करती है. पिछले साल श्रीलंका ने एक लोन मोरेटोरियम की मांग की थी जिसे मंज़ूर करने में भारत सरकार को पांच महीने लग गए जबकि चीन ने बिना वक़्त गंवाए अपने विकास बैंक से अतिरिक्त ५०० मिलियन अमेरिकी डहलर का एक कर्ज़ मंज़ूर किया. चीन के तुरंत फ़ैसला लेने की प्रक्रिया और बड़ी मदद उसे एक ज़्यादा आकर्षक साझेदार बनाती है। लेकिन तब भी चीन के साथ ये आर्थिक मेलजोल श्रीलंका के लिए मुश्किलों के बिना नहीं रहा है। श्रीलंका को कर्ज़ के जाल में फंसने के लिए मजबूर किया गया है और उसे अपनी रणनीतिक संपत्तियों को डेट-इक्विटी स्वैप के ज़रिए बेचना पड़ा है जिसकी वजह से वहां ऐसे क्षेत्र बन गए हैं जहां उसकी अपनी संप्रभुता बेअसर हो गई है। इसकी वजह से मजबूर होकर श्रीलंका को आने वाले समय में अलग-अलग देशों के साथ संबंधों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी और अपनी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करना होगा।

भारत की ताक़त

शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन में चीन के मुक़ाबले भारत काफ़ी मज़बूत साझेदार है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना और कोलंबो प्लान के तहत श्रीलंका के नागरिकों के लिए अलग-अलग तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स में अल्प और मध्यकालीन ट्रेनिंग के लिए ४०० सीटें हैं। २०१७ से श्रीलंका के छात्र नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) और आईआईटी जेईई (एंडवास्ड)

परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। चीन के साथ ये आर्थिक मेलजोल श्रीलंका के लिए मुश्किलों के बिना नहीं रहा है। श्रीलंका को कर्ज़ के जाल में फंसने के लिए मजबूर किया गया है और उसे अपनी रणनीतिक संपत्तियों को डेट-इक्विटी स्वैप के ज़रिए बेचना पड़ा है जिसकी वजह से वहां ऐसे क्षेत्र बन गए हैं जहां उसकी अपनी संप्रभुता बेअसर हो गई है। इन शैक्षणिक आदान-प्रदान को भारत श्रीलंका के संभावित शैक्षणिक ज़ोन में एक इंडियन इंस्टीट्यूट अहफ टेक्नोलहजी (आईआईटी) स्थापित करके और मज़बूत कर सकता है। श्रीलंका के पूर्वोत्तर में कैंडी में भारत तकनीकी और इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर जैसे कि श्रीलंका-इंडिया सेंटर फहर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग (एसएलआईसीईएलटी) स्थापित कर सकता है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका को फार्मास्युटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में गहन सहयोग पर विचार करना चाहिए जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की इस साल श्रीलंका यात्रा के दौरान साझा बयान में एलान किया गया था।

भारत के सहफ्ट पावर का फ़ायदा उठाना

तकनीकी सेक्टर में भारत अपनी इंफहर्मेशन टेक्नोलहजी कंपनियों की श्रीलंका में मौजूदगी का विस्तार करके वहां नौकरियों के अवसर बढ़ा सकता है। ये संगठन हज़ारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के मौक़े बना सकते हैं और इस द्वीपीय देश की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं। ये ऐसा विषय है जिसे दोनों पक्षों ने विदेश मंत्री जयशंकर की यात्रा के दौरान स्वीकार किया था। फार्मास्युटिकल्स के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) के अलावा दोनों पक्ष इंफहर्मेशन टेक्नोलहजी और शिक्षा के सेक्टर में भी ऐसा प्रावधान करने पर विचार कर सकते हैं। अभी श्रीलंका संविधान का मसौदा तैयार करने का कठिन काम शुरू कर रहा है, उसमें भारत अल्पसंख्यकों के अधिकार और अलग-अलग लोगों के प्रबंधन में अपने अनुभव के बारे में बता सकता है. भाषाई और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, शिकायतों के समाधान और प्रतिनिधिक संगठनों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का मसौदा तैयार करने में भारत श्रीलंका की मदद कर सकता है। आख़िर में भारत और श्रीलंका को लोगों के स्तर पर संपर्क को बढ़ाने का तरीक़ा तलाशना चाहिए। श्रीलंका में ज़ूयादातर पर्यटक भारत से आते हैं लेकिन धार्मिक पर्यटन की संभावना की तलाश करना अभी बाक़ी है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए १५ मिलियन अमेरिकी डहलर के अनुदान का ऐलान किया था. इस पैसे का इस्तेमाल कर दोनों देश एक बौद्ध ज्ञान और पर्यटन कहरिडोर का निर्माण करने पर विचार कर सकते हैं. अंत में, दोनों देशों में क्रिकेट के महत्व और मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहिए। श्रीलंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) के साथ साझेदारी के ज़रिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का विस्तार श्रीलंका में करने से आम लोगों के स्तर पर संपर्क को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। श्रीलंका में ज़ूयादातर पर्यटक भारत से आते हैं लेकिन धार्मिक पर्यटन की संभावना की तलाश करना अभी बाक़ी है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए १५ मिलियन अमेरिकी डहलर के अनुदान का ऐलान किया था। इस पैसे का इस्तेमाल कर दोनों देश एक बौद्ध ज्ञान और पर्यटन कहरिडोर का निर्माण करने पर विचार कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग से उन मुद्दों पर चिंता कम नहीं होगी जहां दोनों पड़ोसियो की सोच एक जैसी नहीं है यानी तमिल अल्पसंख्यकों का अधिकार और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में चीन का महत्व. लेकिन इतिहास, सांस्कृतिक नज़दीकी और भौगोलिक मजबूरी भारत और श्रीलंका को इन मुद्दों से आगे बढ़कर स्वाभाविक और स्थायी साझेदार बनाते हैं और नये क्षेत्रों में सहयोग की तलाश करके अपने-अपने देशों की आर्थिक और विकास संबंधी आकांक्षाओं को साझा तौर पर प्रोत्साहन देने के लिए कहते हैं।

द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक स्तर तक बढ़ाना

द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक स्तर तक बढ़ाने के लिए, पत्र में राजनीतिक संवाद बढ़ाने और श्रीलंका से बाहरी रूप से विस्थापित व्यक्तियों/भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता का प्रस्ताव दिया गया है। युद्ध के बाद के वर्षों में श्रीलंका और भारत के संबंधों ने राजनीतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने में एक गति देखी। हाल के वर्षों में कई हाई प्रोफाइल दौरे हुए हैं, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री की २०१४ से तीन बार, २०१६ (जून), २०१७ (मई), २०१५ (मार्च) में श्रीलंका की यात्रा शामिल है। श्रीलंका के राष्ट्रपतियों की भारत यात्राएं २०१६ (नवंबर), २०१६ (मई और नवंबर) और २०१५ (फरवरी) में हुई हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्रियों ने २०१८ (फरवरी और अक्टूबर), २०१७ (नवंबर और अप्रैल), २०१६ (अक्टूबर और मई) और सितंबर २०१५ में भारत का दौरा किया। ये हाई-प्रोफाइल दौरे उच्चतम स्तर पर बढ़े हुए सहयोग के उदाहरण हैं। इन यात्राओं के बाद दोनों देशों के

विदेश मंत्रियों की यात्राएं भी हुईं। राजनीतिक संपर्क बढ़ाने के लिए, अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भारत की संसद में एक कार्यात्मक और जीवंत भारत-श्रीलंका संसदीय मैत्री समूह का पुनर्गठन करना था। इन यात्राओं से द्विपक्षीय संबंधों की एक सकारात्मक छवि पेश करने में मदद मिली है और आर्थिक विकास परियोजनाओं, संपर्क और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग की खोज की गुंजाइश बढ़ी है। इन क्षेत्रों में हुए लाभ की ओर इशारा करते हुए, यह पत्र द्विपक्षीय संबंधों में 'लेन-देन संबंधी दृष्टिकोण' से आगे बढ़ने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस बिंदु को संभवतः कई नाकाम वार्ताओं और समझौतों का जिक्र करते हुए रखा गया था, जिन पर अतीत में हस्ताक्षर किए गए थे, जैसे कि असफल आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता (ईटीसीए) वार्ता, कोलंबो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल मुद्दे के साथ-साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म विकसित करने पर समझौते।

बाहरी रूप से विस्थापित तमिलों का भारत से श्रीलंका में प्रत्यावर्तन

सामरिक ढांचे ने भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की श्रीलंका में त्वरित वापसी को हल करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। पत्र ने जोर दिया कि शरणार्थियों की वापसी से भारत में श्रीलंका की सकारात्मक छवि और श्रीलंका की सुलह प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। चूंकि शरणार्थियों की वापसी के लिए मौजूदा तंत्र धीमा है, इसने प्रस्तावित किया कि विस्थापित व्यक्तियों के स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी, जिसे भविष्य में भारत के साथ साझा किया जाएगा। २००६ में युद्ध की समाप्ति का नतीजा उन श्रीलंकाई तमिलों के लिए एक सुरक्षित, स्थिर, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण नहीं बना सका, जो श्रीलंका सरकार और लिबरेशन टाइगर्स अहफ़ तमिल ईलम (लिट्टे) के बीच लंबे समय तक संघर्ष (१६८३-२००६) के कारण देश से भाग गए थे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में अपने देश वापस जाने के लिए शरणार्थियों की अनिच्छा के कारण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में समय लग सकता है। वर्तमान में, भारत में लगभग एक लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (न्छभ्त्ब्) वर्तमान में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया में लगी हुई है। लेकिन श्रीलंका में राजनीतिक स्थिति के कारण प्रक्रिया वास्तव में धीमी है। २००२ के बाद से केवल १७,७१८ शरणार्थी श्रीलंका लौटे हैं। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने शरणार्थियों के लिए ₹३१७.४ करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, फिर भी यह मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है।

आर्थिक सहयोग

वैष्विक महामारी से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। देश के राजस्व के मुख्य स्रोत, पर्यटन क्षेत्र में गिरावट देखी गई और इसी तरह देश के निर्यात में भी गिरावट आई। भारत २०२० में चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा, और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन तीन व्यापारिक भागीदारों के साथ कुल व्यापार २०१६ के १२.६ बिलियन अमेरिकी डहलर से घटकर १०.५ बिलियन अमेरिकी डहलर हो गया है। इसलिए, श्रीलंका का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए अपने व्यापार की मात्रा के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (थ्क्प्) को बढ़ाने पर रहा है। २००५ से २०१६ की अवधि में श्रीलंका में भारत से एफडीआई १.७ बिलियन अमेरिकी डहलर था। दस्तावेज़ में निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ भारत में श्रीलंका की बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने का विवरण दिया गया है। यह श्रीलंका में भारत के मौजूदा निवेश जैसे कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, त्रिंकोमाली अहयल टैंक फार्म, बिजली क्षेत्र में सहयोग और विकास सहयोग के तहत परियोजनाओं पर फहलो अप कार्रवाई का भी प्रस्ताव रखता है। इन परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के अलावा, श्रीलंका के निवेश बोर्ड (बीआईओ) ने वर्ष २०२१ के लिए ३०० मिलियन अमेरिकी डहलर और वर्ष २०२२ के लिए २५६ मिलियन अमेरिकी डहलर का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें अहटो घटक, भोजन प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और वस्त्र शामिल हैं। आईसीएस पत्र आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ जुड़ने का भी प्रयास करता है। यह दस्तावेज़ में श्रीलंका द्वारा निर्धारित 'समृद्धि और वैभव के दृश्य' के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को साकार करने में मदद करेगा। श्रीलंका में पिछली यूनिटी सरकार ने सभी पांच दक्षिण भारतीय राज्यों को शामिल करते हुए भारत के साथ ५०० बिलियन अमेरिकी डहलर के संभावित व्यापार की कोशिश की। हालाँकि ईटीसीए प्रस्ताव, जिसे भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, अमल में नहीं लाया जा सका। सेवाओं

में व्यापार के खंड पर कुछ पेशेवर समूहों द्वारा समझौते के विरोध और केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता ने वार्ता को कमजोर कर दिया।

फ्रेमवर्क दस्तावेज़ में ईटीसीए के बारे में तो उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसने भारत में श्रीलंका के निर्यात को प्रभावित करने वाले मुद्दों के रूप में 'संरक्षणवाद, सीमित बाजार पहुंच और भारत में अप्रत्याशित नियामक वातावरण' के मुद्दे को उठाया। २०२० में, भारत में श्रीलंका का निर्यात उसके कुल निर्यात का १६ प्रतिशत था, जबकि भारत से आयात लगभग ६ प्रतिशत था। वर्ष २०२१ के लिए निर्धारित व्यापार लक्ष्य ६२१.६ मिलियन अमेरिकी डह्लर और वर्ष २०२२ के लिए ६७४.१५ मिलियन अमेरिकी डह्लर है। भारतीय निवेश को लेकर पिछले अनुभव के साथ-साथ आशंकाओं और श्रीलंका के व्यापार संघों द्वारा श्रीलंका के सेवा क्षेत्र जैसे व्यापार के लिए क्षेत्रों को खोलने के कारण, यह देखना बाकी है कि दोनों सरकारें भविष्य में आशंकाओं को कैसे दूर करेंगी।

रक्षा और हिंद महासागर सुरक्षा सहयोगः एक नया जोर

हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है। भारत सबसे पहले पहुँचने वाला देश रहा है और उसने २००४ की सुनामी जैसी श्रीलंका की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और हालिया उदाहरण सितंबर २०२० में श्रीलंका के पूर्वी तट पर तेल रिसाव को संभालने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की तैनाती है। चरमपंथी तत्वों द्वारा श्रीलंका के चर्चों और होटलों पर अप्रैल २०१६ को किए गए ईस्टर संडे हमलों से पहले और उसके बाद खुफिया सहायता प्रदान करने में भारत ने श्रीलंका सरकार की मदद करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संबंधों के सुरक्षा आयाम केंद्र में हैं और भारत ने २०१६ में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर रोक के लिए विशेष ऋण के रूप में ५० मिलियन अमेरिकी डह्लर प्रदान किए हैं। दोनों देश मित्र शक्ति के साथ-साथ क्षमता निर्माण अभ्यास जैसे कई संयुक्त सैन्य अभ्यासों का हिस्सा रहे हैं। क्षेत्र में अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए हिंद महासागर की सुरक्षा एक प्राथमिकता बन गई है। यह सदियों से समुद्री व्यापार के केंद्र में रहा है। इस क्षेत्र में श्रीलंका और भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, दोनों देशों ने इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा तथा नौवहन की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। दोनों हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के सदस्य हैं और इस क्षेत्र में समुद्री रक्षा एवं सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में योगदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद जैसे पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों के रूप में आम चुनौतियों ने सुरक्षा क्षेत्र में एक साथ काम करने की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। हाल के महीनों में कुछ उदाहरण इस अबाध समुद्र में सुरक्षा समस्या की पुष्टि करते हैं। पहला, सितंबर २०२१ में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा ६०० किलोग्राम से अधिक हेरोइन की जब्ती और सात पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी और दूसरा मार्च २०२१ में मछली पकड़ने वाले श्रीलंकाई जहाज द्वारा ले जाए जा रहे ३०० किलोग्राम से अधिक हेरोइन, पांच एके-४७ राइफल और १,००० राउंड गोला-बारूद की जब्ती है।

सुरक्षा क्षेत्र में हितों का सम्मिलन भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित विभिन्न बैठकों में प्रकट होता है। छह साल के अंतराल के बाद, २६ नवंबर २०२० को कोलंबो में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (छै।) स्तर की त्रिपक्षीय बैठक हुई। इस क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों पर विचार करते हुए, भारत, श्रीलंका और मालदीव ने खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरता और मनी लह्न्ड्रिंग जैसे मुद्दों से निपटने में सहयोग को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की है। ६ अगस्त २०२१ को श्रीलंका द्वारा आयोजित उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक के दौरान सहयोग के सुरक्षा पहलू को दोहराया गया। इसलिए, आईसीसी पत्र ने सामान्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए श्ट्रोइकाश जैसे तंत्र को विकसित करने और तलाशने का प्रस्ताव रखा। इस तंत्र को २००६ में युद्ध के अंतिम चरण के दौरान स्थापित किया गया था। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन, राजदूत शिव शंकर मेनन, विदेश सचिव और रक्षा सचिव विजय सिंह ट्रोइका का हिस्सा थे। श्रीलंका की ओर से बासिल राजपक्षे, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के वरिष्ठ सलाहकार; गोटाबाया राजपक्षे, रक्षा सचिव; और श्रीलंका के राष्ट्रपति के सचिव ललित वीरातुंगा 'ट्रोइका' तंत्र का हिस्सा थे। श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच युद्ध के दौरान भारत-श्रीलंका संबंधों से निपटने के लिए ट्रोइका व्यवस्था उनकी संबंधित सरकारों की ओर से निर्णय ले सकती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास की सुविधा, प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं की संख्या में वृद्धि के अलावा, पत्र भारत में

श्रीलंका के उच्चायोग में रक्षा सलाहकार के कार्यालय को मजबूत करने का प्रयास करता है।

महासागर संसाधनों की रक्षा करनाः राजनीति और आजीविका के बीच फंसा

दोनों देशों के बीच भौगोलिक निकटता ने अवसरों के साथ-साथ चुनौतियां भी प्रदान की हैं। समुद्री सीमा का मुद्दा १९७४ और १९७६ में पाक खाड़ी, पाक जलडमरूमध्य और बंगाल की खाड़ी में सुलझाया गया था। तथापि, समुद्री संसाधनों को साझा करना, विशेष रूप से मछुआरों का मुद्दा, द्विपक्षीय सहयोग में एक चुनौती बना हुआ है। मत्स्य पालन जैसे मुद्दे को हल करने के लिए एक तंत्र मौजूद है, संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) जिसे २०१६ में स्थापित किया गया था। दोनों पक्ष नियमित परामर्श के ज़रिये मानवीय आधार पर इस मुद्दे को हल करने के लिए सहमत हुए। दोनों पक्षों के मछुआरों की गिरफ्तारी के साथ-साथ नौकाओं की जब्ती को नियमित तरीके से निपटाया गया। दिसंबर २०२० में वर्चुअल तौर पर आयोजित चौथी जेडब्ल्यूजी बैठक में, जब्त की गई नौकाओं की शीघ्र रिहाई की आवश्यकता के साथ-साथ गश्त में नौसेना और तट रक्षक के बीच सहयोग पर चर्चा की गई। भारत सरकार, तमिलनाडु और पुडुचेरी ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकल्प चुनने के लिए मछुआरों को प्रोत्साहित करके पाक खाड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ने के दबाव में विविधता लाने और उसे कम करने के उपाय किए हैं। समुद्री शैवाल की खेती, समुद्री कृषि और जलीय कृषि गतिविधियों की किस्मों के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इन उपायों के बावजूद, २०१९ और २०२० में, लगभग २८४ मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और कुल ५३ भारतीय नौकाओं को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा जब्त किया गया। जनवरी २०२१ में, एक भारतीय ट्रॉलर के श्रीलंकाई नौसेना के जहाज से टकरा जाने से ४ भारतीय मछुआरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद श्रीलंका ने एक स्थायी समाधान खोजने के लिए तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की। आईसीएस पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्रीलंका दोनों पक्षों के मंत्रालयों के साथ-साथ मछुआरा संघों को शामिल करते हुए एक प्रस्ताव तैयार करेगा और नीचे की ओर मछली पकड़ने तथा अवैध, बिना सूचना के और अनियमित आईयूयू मछली पकड़ने से होने वाले पारिस्थितिक नुकसान को भी उजागर करेगा।

महासागरीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में पत्र में उठाया गया दूसरा मुद्दा महाद्वीपीय किनारों के छोर का परिसीमन करना था। भारत और श्रीलंका के संबंधित दावों को संयुक्त राष्ट्र के कॉन्टिनेंटल शेल्फ (सीएलसीएस) की सीमाओं पर गठित आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अतीत में, भारत का पक्ष रहा है कि वह इस मुद्दे पर पारस्परिक रूप से लाभप्रद समाधान पर पहुंचने के लिए द्विपक्षीय चर्चा को प्राथमिकता देगा। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के समझौते के वक्तव्य (एसओयू) (अनुबंध ॅ में) के तहत दोनों देश संयुक्त लाभार्थी हैं। फिर भी, हाल के वर्षों में द्विपक्षीय चर्चाओं में इस मुद्दे को ज्यादा नहीं उठाया गया है। सीएलसीएस भविष्य में इसकी प्रस्तुति पर आदेश देगा। यह देखा जाना बाकी है कि क्या दोनों देश भविष्य में उसी प्रकार से चर्चा शुरू करेंगे, जैसा कि पत्र में प्रस्तावित है।

निष्कर्षः-

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं खराब हालात में श्रीलंका की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत श्रीलंका के साथ हमेशा 'पड़ोसी धर्म' निभाता रहा है। आईसीएस पत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों में आम चिंता के मुद्दों को एक साथ रखता है। श्रीलंका की वर्तमान सरकार का मुख्य जोर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर रहा है। यह पत्र ऐसे समय में आया है, जब श्रीलंका जबरदस्त आर्थिक दबाव में है। एक छोटी अर्थव्यवस्था जो पर्यटन, निर्यात, निवेश और संकीर्ण उत्पादन क्षमता के ज़रिये राजस्व पर निर्भर है, और उसपर से बढ़ता कर्ज, महामारी का समय कठिन था। श्रीलंका का कुल बकाया कर्ज ३५.१ अरब अमेरिकी डॉलर है। इसलिए वह आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए हर संभव रास्ते तलाश रहा है। आर्थिक मुद्दों के अलावा, देश पर पश्चिम से सुलह पर प्रगति दिखाने का भी दबाव है। ईयू जीएसटी+ जैसी व्यापार रियायतों को मानवाधिकारों की प्रगति से जोड़ा गया है। इसलिए, श्रीलंका को भारत सहित अपने विदेशी संबंधों में एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा।

संदर्भ-

1- "Sri Jayewardenepura Kotte"- Encyclopædia Britannica- vfHkxeu frfFk 12 May 2020
2. "Colombo"- Encyclopædia Britannica- vfHkxeu frfFk 12 May 2020
3. Roberts] Brian (2006)- "Sri Lanka: Introduction"- Urbanization and sustainability in Asia: case

studies of good practice- ISBN 978&971-561-607-2
4. Jack Maguire (2002)- Essential Buddhism: A Complete Guide to Beliefs and Practices- Simon and Schuster- p- 69- ISBN 978-0-671-04188-5-"---the Pali Canon of Theravada is the first known collection of Buddhist writings ---"
5. "Religions – Buddhism: Theravada Buddhism"- BBC- 2 October 2002.